間という	TAX 0/0 THE COMMISSIONED MARKET द्वितीय तत. जी ए रेस कोर्स रिंग	. वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीन उत R (APPEALS), GST & CENTRAL म टी भवन / 2 ³⁴ Floor, GST Bhavan, रोड, / Race Course Ring Road, <u>रिट / Raikor – 360 001</u> 2441142 Email: cesappealsmjkou	EXCISE,	
টা	स्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-			
Ð,	अभीतः (काहतः संगुजाः) Appeal (File No	म्यूल आदेश स (1)111 हेल	विज्ञानः ।	
	V2/207 to 209 /RAJ/2016	02 & 03/ADC/BKS/2016-17	16.05.2016	
g	अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No	a.):		
	RAJ-EXCUS-000-/	APP-032 TO 034 -201	7-18	
	आदेश का दिनांक / 09.08.2017 Date of Order:	जारी करने की तारीख ! Date of issue:	11.08.2017	
	कुमार संतोष, आयुक्त (अपील), राजको	ट द्वारा धारित /		
	Passed by Shri Kumar Santosh,	Commissioner (Appeals), R	ajkot	
T.	अगर आयुन्दर्ग संयुक्त आयुक्ता आयुक्त आयुक्त अन्त्रक अन्द्रीत उत्पद भुक्ता धेलका, राजवटेट / जनवता / नागीतव्यः द्वारा उपातिधिन आपि सूत्र आदेश में सुनित / Ansing out of above mentioned CiO issued by Addition/RointDopsey/Assistant Commissioner. Central Encise / Service Tax,			
т	Hajkot / Jamnagar / Gandhidhani : अपीलकर्ता & प्रतिवादी का लाम एवं पता /	Nama&Address of the Annalla	nto A December 1	
	 Shri Rajanbhai Santoki, Parte Shri Ashokbhai L. Patel, Part 	ivam Chowk Gondal Road,Rajkot ier, M/s. F.averi Enginners, ner, M/s. Kaveri Enginners,	-360007	
	हम आदेश(आगिम) से व्यक्ति कोई व्यक्ति किंग्रालीतिक तरीक Any person aggnieved by this Order in Appeal may t	c at surglass collition(f) / collition in prate suffic We are opposid to this appropriate authority is	i zbirt wa amon ‡s/ i the following way.	
A)	सीमा गुरुक जेवडीय उत्पाद गुरुक एव संसक्षा अपीसेंच रव अंतमेन एव चितन अधिजिक्ता 1994 की पता 86 के आसंत Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appetia Finance Act, 1994 an appeal lies to:	त विवयतिविधान जनत की उस समय्ती है ।/		
0	वंगीकरण जुल्यांकल से सम्बद्धिधन लागे लागले छोटा गडवा, ब 2, आर. के. पुरस, नहे दिल्ली, को की वासी पाहिए एँ The special bench of Customs, Excise & Service 7 matters relating to classification and valuation			
10	उपरोक्त गरिएछेट 1(a) में बनाए तए अपीली के अलावा ते (जिस्टेट) की परिषय बीबीय पीठिका , ट्रविलीत तता, बहुमानी To the West regional bench of Customs, Excise & Asarwa Ahmedabad in cash of appents other than a	NAM MADE HEREINES AD AT THE UTER I/		
40)	अणीमीथ स्थापाधिकरण के तस्वत अणीत प्रस्तुत करने के लिए रूपे एपन EA-3 को धार प्रतियों में उन्हें किया ज्ञाना धाहित अपि तमावा नया जुस्तोस, स्थल 5 लाख था उपनी पता, 5 ला स्पर्य, 5,000/- रुपर अपना 10,000/- रुपर का सिनादीय स्थापाधिकरण की कास्ता के सहापक रविश्वरात के लास त कित संबंधित युग्पट का सुलतान, बीक की उस माखा में होना साहित किए आसेइस-पड के साथ 500/- स्थल का डिप्रांतिज सुल्क उस्त	केन्द्रीम उत्पाद गुल्क (अभीत) क्रियमामजी, 2001, 1 1 इसमें से कम में कम एक प्रति के तरा, जहां उ स रुपए मा 50 लाख लेपए तक प्रधान 50 लाख क जम्म मुल्क की प्रति सलस्त जरे। जिस्तीरेश म 1 में सार्वाजना क्षेत्र के वैक द्वारा जारी रेस्ट्रांकिन में प्रका कर्मीरेश अपीक्षीय जास्तरविद्याल की स्थान दि	गण्ड, मुल्क की मॉन आगत की जॉन गए में अधिक है तो कमल 1,000 एक का मुख्यपत संबधित अधीर्थन कि वापन देवता विकार जन्म भाषित :	
	The appeal to the Appellate Tribunal shall be fixed Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompt 1.000/- Rs.5000/-, Rs.10.000/- where amount of di above 50 Lac respectively in the form of crossed I sector bank of the place where the bench of any in is situated. Application made for grant of stay shall	iment logarist one which at least should be uty domand/imenest/imenaty/imfond is upto bank draft in favour of Asis. Registrer of to ominated public sector bank of the stace v	I accompanied by a fee of Rs. 1 Loc. 5 Loc to 50 Loc and smith of any permated addi- control of any permated addi-	
8)	अभीसीय स्वाम्याधिकरण के समल अभीत, वितन अधितियल, निष्पोरिस प्रयन 5.1.5 में सार पतिथी में की जा सकेवे एन (उनसे से एक पति प्रमाणित होनी यहिए) और इससे से का मुम्बी साएस 5 लाख पा उससे का निर्धारित जान प्राप्त पा 50 संपर्ध प्राप्तन 10,000/ स्पष्ट का निर्धारित जान शुरूत के पति संपायक रजिरदार के लाभ से विश्वी भी जावीजिनन तरह के बैच के की उस साफा में होना पाहिए जहा संवर्धित अप्रित अप 500/ स्पष्ट का निर्धारित शुरूत अस काला होना //	1984 की फाल 36(1) के अन्तर्भन संसाहन जिल्लान उसके साथ जिंहा आदेश के विरुद्ध उच्चेल की गई व से क्या एक पति के प्राण, जना गेलकर की आं गोख गांग नवे अपका 20 लाइ रुपए से अधिक 1 1 साधन की डिस्टीनिंग सुरुष कर अन्तराज, संसीरित द्वारा जारी सिल्डिंग के बापल द्वारा किया जाना	(द), उसकी प्रति साथ में माम्रक के त्याज की म्लेन और क्लामा गया तो करूका 1,000/ वर्षा, 5,000/ अपिलेग स्थायाधिकरण की शाम्र के प्रतिय 1,000/ वर्षाया कर का माल्या	
	The appeal under sub section (1) of Section 81, quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under to copy of the order appealed against toos of which	at the Physics Act. 1994, to the Appel	late Tribunal Shall be filed a	

1

ļ

copy of the order appealed against tone of which shall be consider copy) and should be accompanied by a fees of Fis. 1000/- where the amount of service tax 3 interest domanded 8 privatly levied of Hs. 5 Lakins or less, Rs.5000/- where the amount of service tax 3 interest domanded 8 privatly levied of Hs. 5 Lakins or less, Rs.5000/- where the amount of service tax 3 interest domanded 8 privatly levied is none than that but not exceeding Rs. Fifty Lakins, Rs.10,000/- where the amount of service tax 3 interest domanded 8 privatly levied is none than that not exceeding Rs. Fifty Lakins, Rs.10,000/- where the amount of service tax 3 interest tax analy invited is none than that not exceeding Rs. Fifty Lakins, Rs.10,000/- where the amount of service tax 4 interest tax 8 interest tax 5 privatly levied is none than that suppose, in the form of consisted bank dual is favour of the Agestant Rogentum of the bench of commisted Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated if Agestant Rogentum for stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

There and there, 1994 with user of the surveyed (2) on (2A) we worker call with and and an enter the method (1994, we find 9(2) on (2A) we may any any find the second of the second sec

1

 $\overline{(n)}$

113

N

19

तीया शुल्क, केल्द्रीय उत्पाद शुल्क एव संवाकत अमेलिय अधिकरण (संस्टेश) के पति अपीलों के लयाने से केल्द्रीय उत्पाद शुल्क ऑपेलियम 1944 की धारा उदेश्य के जनमेत, जो की जिल्लीय अपीजियम 1994 की घारा 83 के अनमेत सेवाकर को भी व्यमू की नई है, इस आदेश के पति अमीलिय प्राधिकरण में अमील करने लमय उत्पाद शुल्कारोता का साम के 10 प्रतिकान (10%), जब मांग एवं जुसीना विवादित है, या जुमीना, जब केवल जुमीना विकादित है, पर मुम्लास किला जाए काली कि इस पाए के अनमेत उत्पा कि जाने जाती अमीशित देव पत्रि एक करोड़ क्या में अपिक ज हो।

संपर्धाय अपनाह सुरक्त १४ मंत्रावर के अंत्रणेत 'सांग किंग गए सुरक्ष' से सिरस सामित है

- भाग ११ की के अन्तर्गल गावर
- (ii) तेनवेट जमा की में। गई गला तोंग
- (a) सेमलेट जमा विवासवाकी के प्रियम 6 के अल्लेज देश रक्षा

्बमारी यह कि इस प्रतार के पावधान वित्तीय (स. 2) अंग्रेजियम 2014 के आरम से पूर्व किसी अपीसीय प्राधिकारी के समक्ष विधारणीन स्वागत जन्मी पत्र उपीस को लागू नहीं होने?

For an appeal to be find before the CESTAT, under Section 35F of the Central Exceler Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section d3 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall be before the Triburul on payment of 10% of the duty intravided where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in texpute, provided the amount of pre-dupnet payable would be subject to a celling of Fis. 10 Crotes, Upday Central Exceler and Service Tax. 'Duty Demanded' shall include

- impuni disermised under Section 11 D.
- 64 Amount of enonyous Cervin Crodit laker.
- (a) amount payable under Rute 6 of the Cervoit Cledit Ruses.

 provided turther that the provisions of this Section shall not apply to the stary application and appeals pending before any appallate authority prior to the commencement of the Emance (No 2) Act, 2014.

(C) attent an unifier solution (C) Revision and concerning

Revision application to Covernment of tudia: इस आदेश की पुर्वात्रिया प्राणिका विवयतितित सामली में केंद्रीय तथाई सुपंक अधिविधान, 1994 की घंगा 35EE के प्रथम पालुक के अतमेत अवर नतित आदय सांखार, पुनीलिय आवहन इंन्स्ड्री विद्य संचलप, गालक विवया, योधी सांतिय जीवन दीय अवन, संसद माने, नई दिल्ली-110001, की विवया जाना पालिए 7

A sevision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue 4th Ploar, Jervan Deep Building, Parlament Stear, New Dethi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B (bit).

- III star & feall genetic is much if, and generic feall and et fail entant if and or an it found to the star of the star of
- (ii) accer & way field crez is ets #1 fielder et c2 acce & following is upper etc. Arm it is avoid accer by a serie & go (花花) # around #1, at etc.r & etc.r field crez is #1 follow field and #1.1 In case of rebars of both one is goods exported to any country or series outside india of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exposed to any country or territory outside india.
- (iii) यदि उत्पाद शुरूक का मुलतान किंग किंना कारत के नएए, नेपान पा मुटना की साथ नियोग किंगा गया है। /
- In case of goods exposed ounide India export to Repail or Bhutan, without payment of duty
- (iv) applitude screec & screece give & specifie & Det of st(2) Adic see aftitibute the set fittback control & oper anex 40 vg it after the set of annual fitter and the state of the set of the set
- (v) Studies added 40 of sitial and some EA-6 #, or 41 kindla similar syme (artis) Blaurach, 2001, 4 Blaur 9 & addet falilities f, ga ante 4 within 40 and 4 and only 1, routes antes 4 million and a site 5 with anter 40 of 2 site and 4 and only of the anter 41 and anter 41 anter 41 and anter 41 anter 4
- (vi) पुनीवल्ग आवेटन के साथ जिन्नविधित विश्वतित शुरुक की अटावली की जानी पाहिए। उन्हों सालन प्रकार का साथ रुपये या उन्हों का ही तो रुपये 2000 का भुगतान किया. जाए और पटि सालन स्वया एक लाख रुपये से उनाटा हो तो रुपये 1000 / का मुलतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 2001 where the amount availand in Ruppes One Lac or less.

The revision application shall be accompanient by a fee of PS 2001 where the amount involved in Rappes One Lac or less, "and Rs. 10007 where the amount involved is more than Ropers One Lac.

- (D) If the bidge is with a weak a second by the construction of the appeal of the second by the s
- (E) constrained special special and the second special is asympthetic and an angle the second second second special spectrum and the second second
- (F) aftair epise, wedite since some on Ameri orbital consultance (and fifth) foromolit, 1982 it offen on one analysis another attained at addating and and foroid its decide some somethic films and \$1.7. Attention is also motion to the odes covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appendiate Tribunal (Procedure) Roles, 1982.
- (G) stud schäre ontrach et sche ontan ege of estimation internet aft adapte sustail & Dre schered Barette beoge www.cbec.gov.m.et.cts.uent.s.i.i.



:: ORDER IN APPEAL ::

The appeals listed herein below have been filed by the assessee/persons named against Order-In-Original No. 2 & 3/ADC/BKS/2016-17 dated 16.05.2016 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Additional Commissioner, Central Excise, Rajkot (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority").

Sr. No.	Name of the Appellant	Appeal File No.	Appellant No.
01.	M/s. Kaveri Engineers, Shivam Industrial Main Road, Plot No. 17, Survey No. 29, Vavdi, Near Falcon Pump, Shivam Chowk, Behind Hotel Krishna Park, Gondal Road, Rajkot - 360 007	V2/207/RAJ /2016	Appellant No. 1
02	Shri Rajanbhai Santoki, Partner, M/s. Kaveri Engineers, Rajkot.	V2/208/RAJ /2016	Appellant No. 2
03	Shri Ashokbhai L. Patel, Partner, M/s. Kaveri Engineers, Rajkot.	V2/209/RAJ /2016	Appellant No. 3

 Since the issue involved is common in nature and connected with each other, the same are taken up together for disposal.

The facts of the case are that the appellant no.1 is a partnership 3 firm, engaged in the manufacture of Architectural Hardware items viz. Door Closure, Floor Spring, etc. falling under Chapter 83 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985. A search was carried out by the Officers of the Preventive Branch of Central Excise, Rajkot on 10.10.2014 and recovered incriminating documents, which revealed that the appellant were not holding central excise registration and had not maintained any statutory records; that they had clandestinely cleared their finished excisable goods without invoices and without payment of Central Excise duty; that they maintained private diaries to monitor their transactions made in cash; that in the said diaries, "P" denoted for "Pakka Bills" and "K" denoted for "Kachcha Bill"; that the private diaries were placed under seizure; that the statements of appellant No. 2, appellant No. 3 were recorded, wherein they admitted central excise duty liabilities for such clandestine clearances without raising invoices even after crossing the value based exemption limit; that the statements of buyers namely; Shri Sanjay P. Faldu, Partner, M/s. Hardware Hub, Surat; Shri Rakesh N. Hinjrajiya, Partner, M/s. Italian Home Décor, Indore; Shri Devendra U. Kamani, Proprietor, Mi/s. Amtop Industries, Rajkot were also recorded wherein they admitted purchases of these goods without payment of duty and without receipt of invoices; that the investigation revealed that the appellant had maintained three private diaries for clandestine clearances to monitor their sales proceeds and raw material purchase payments; that they entered their entire sales records in the 'Ughrani' (receivable) book i.e. with invoice and without invoice sales; that their sales turnover for the financial year 2014-15

was more than Rs. 1.50 crore; that the aggregate clearance value of all entries recorded in Ughrani books comes to Rs. 3,04,53,768/- for the FY 2014-15; that they subsequently obtained central excise registration; that the finished goods namely 500 Nos. of Door Closure and 100 Nos. of Floor Spring totally of Rs. 2,55,000/- were placed under seizure on 10.10.2014.

3.1 The investigation led into issuance of Show Cause Notice No.V.83(4)-11/MP/D/14-15 dated 01.04.2015 proposing confiscation of the seized goods; imposition of penalty on appellant No. 1 under Rule 25 of Central Excise Rules, 2002 and imposition of penalties on appellant No. 2 & 3 under Rule 26 of the Rules; and also Show Cause Notice No. V.83/AR-V/Div-I/Rjt/BKS/ADC/126/2015-16 dated 31.12.2015 was issued demanding central excise duty of Rs. 19.10,086/- under Section 11A (4) of the Central Excise Act, 1944 alongwith interest under Section 11AB (now Section 11AA) of the Act and imposition of penalty under Section 11AC of the Act readwith Rule 25 of the Rules and appropriation of Rs. 20,00,000/- paid during the course of investigation.

3.2 Both of these SCNs were adjudicated by the lower adjudicating authority vide impugned orders wherein he ordered confiscation of the seized goods under Rule 25 of the Rules and gave an option to pay redemption fine of Rs. 65,000/- in lieu of confiscation under Section 34 of the Act; confirmed demand of central excise duty of Rs. 19,10,086/- under Section 11A(4) of the Act; also confirmed recovery of interest under Section 11AB (now Section 11AA of the Act; appropriated Rs. 20 lakhs against duty and interest so confirmed; imposed penalty of Rs. 19,10,086/- upon appellant No. 1 under Section 11AC of the Act read with Rule 25 of the Rules; imposed penalty of Rs. 4,00,000/- each upon appellant No. 2 & 3 under Rule 26 of the Rules and imposed penalties of different amounts upon the buyers of Appellant No. 1 under Rule 26 of the Rules.

4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant no. 1 filed appeal alongwith application for condonation of delay in filing the appeal, *interalia*, on the following grounds that:-

(i) The appellant were following the practice of accounting of the goods as and when goods are to be dispatched; that there is plethora of judgments available under which it has been categorically held that the goods not removed from the factory even though the goods has not been accounted for cannot be seized and confiscated and also cited judgments; that no finding is offered by the lower adjudicating authority on the facts submitted by the appellant or any citation confirming confiscation given by the lower adjudicating authority; that the appellant requested to set aside the order of confiscation and redemption fine.



Page No. 4 of 13

(ii) Mere admittance during investigation is not sufficient evidence to prove clandestine removals; that the investigating authority failed to adduce proof regarding clearance of goods i.e. transport receipt under which goods were transported; that investigating authority has not made to go to the transporters/truck driver etc. and also not visited ultimate buyers to arrive at the truth; that the investigating officers should have verified the purchase of inputs without payment of duty; that no positive evidence of inputs purchased by the appellant without payment of duty has been adduced; that mere presumption is not being sufficient ground to prove suppression of production and subsequent clandestine removal.

(iii) As regard to imposition of penalty on partner, the lower adjudicating authority has relied upon the decisions which pertain to the personal penalty imposed on Director; that Director is separate legal entity whereas partner is not separate legal entity; hence imposition of penalty on partner as well as partnership firm is not legal & proper.

4.1 Being aggrieved with the impugned order, the appellant no. 2 & 3 filed appeals alongwith applications for condonation of delay in filing the appeals, *interalia*, on the grounds that under law of partnership, term having no legal existence apart from its partners and merely a compendious name to describe partners as distinguished from a company which stands as separate entity distinct from its shareholders; that where no specific rule is attributed to the partner in the firm, then once firm has already been penalized, separate penalty cannot be imposed upon the partner because a partner is not a separate legal entity and cannot be equated with employees of a firm; that the appellants relied decisions in the cases of S.R. Lites reported at 2013 (296) ELT 498 (Tri. – Del.); Arihant Synthetics reported at 2013 (298) ELT 278 (Tri. – Ahmd.); Pravin N. Shah reported at 2014 (305) ELT 480 (Guj.).

4.2 It was also submitted that it is well settled position of law that when main noticee admitted the liability and also made payment of duty, there is no requirement of issuance of Show Cause Notice and proceedings initiated is deemed to be concluded against the co-noticees also; that no separate penalty on partner is required to be imposed when penalty under Rule 25 has already been imposed on the partnership firm.



5. Personal hearing in the matter was held 04.07.2017 which was attended by Shri Rushi Upadhyay, Chartered Accountant on behalf of the appellants no. 1 to 3, who reiterated the grounds of appeal and submitted that Rs. 20 lakhs have already been deposited by the appellant as law abiding assesse. He contended that in respect of clearances under Kachcha Bills, they have not collected duty separately hence cum-duty price benefit should be extended to them as per available case laws. He undertook to submit detailed calculation of duty liability, which they have pointed out in Para 7.3 of the Appeal Memorandum.

5.1 He also submitted that they being a partnership firm, penalty can't be imposed on firm as well as other appellants as per orders passed by CESTAT & High Court in various cases submitted i.e. S.R. Lites, Arihant Synthetics, Pravin N. Shah, etc.

5.2 The Chartered Accountant vide letter dated 03.07.2017 reiterated the contents of para 7.3 of the appeal memorandum and submitted that the department has covered Pakka Bills as well as Kachcha Bills while calculating the value and duty thereon; that pakka bills include other taxes also like VAT and cumtax value is required to be taken to arrive at the correct assessable value; that likewise in case of Kachcha bills, cum-duty benefit should be given to arrive at the assessable value; that he submitted bill-wise value of goods cleared under retail/tax invoices where VAT/CST has been charged and also submitted revised calculation of value and duty for deciding the case.

Findings:

0

6. I have carefully gone through the facts of the case, impugned order, grounds of appeals and submissions made by all the appellants. The appellants have filed applications for condonation of delay in filing the appeals explaining the reasons for delay of about 25 days as non availability of authorized person. The Commissioner (Appeals) has power to condone delay upto 30 days. I am, therefore inclined to condone the delay and proceed to decide the appeals on merits.

6.1 I find that the issues to be decided in the present appeals are that (i) whether the impugned orders confiscating the seized goods in question and imposing redemption fine of Rs. 65,000/- in lieu of confiscation is proper or not; (ii) whether the confirmation of demand of Rs. 19,10,086/- under Section 11A(4) of the Act is proper or otherwise; (iii) whether benefit of cum-duty price can be extended to the appellant No. 1; and (iv) whether penalty on partner needs to be imposed under Rule 26 of the Rules or otherwise.

Page No. 6 of 13

7 The appellant has argued that the seized goods had not been removed from the factory and that the goods inside the factory cannot be seized and confiscated and thereby no redemption fine in lieu of confiscation can be imposed. I observe that the facts of the case very clearly establish that the appellant No. 1 was indulging into clandestine production and clearance thereof, was also preparing Kachcha Bills to evade payment of Central Excise duty. The lower adjudicating authority has clearly held that the seized goods were not accounted for by the appellant No. 1 in their statutory records and would have been cleared clandestinely, had the departmental officers not visited the factory premises. I find that clause (b) of Rule 25(1) of Central Excise Rules, 2002 provides that if any manufacturer of excisable goods does not account for any excisable goods manufactured by him, then all such goods shall be liable to confiscation. I also find that the investigation of the case has proved that the appellant No. 1 had cleared the excisable goods valued at Rs. 3,04,53,768/- during the financial year 2014-15 till the date of search on 10.10.2014, out of which many removals were made without accounting for the actual production and clearance of excisable goods, without raising of central excise invoices and without payment of central excise duty. Even the appellant had not obtained central excise registration till the factory premises were visited by the departmental officers on 10.10.2014. even though the aggregate value of the clearances of excisable goods had crossed the threshold limit of exemption. The seized goods were also liable for confiscation in terms of clause (c) of Rule 25(1) of the Rules as they were continuously engaged in manufacture of excisable/dutiable goods without having applied for the registration certificate. Thus, I find that the lower adjudicating authority has rightly ordered for confiscation of the seized finished goods found unaccounted at the time of search.

7

7.1 The value of the confiscated goods had been found at the time of seizure, at Rs. 2.55 lakhs which involved Central Excise duty of Rs. 31,518/- (@12.36 Adv.). Hence, redemption fine of Rs. 65,000/- is appropriate and not excessive.

8. It has also been argued by the appellant No. 1 that mere admittance during investigation is not sufficient evidence to prove clandestine removals; that the investigating authority has failed to adduce proof regarding clearance of goods, namely, transportation of goods, purchase of raw materials without payment of duty, etc. I find that during search of the factory premises of appellant No.1 on 10.10.2014, incriminating documents/records, namely, Diaries (Ughrani books) were resumed under Panchnama proceedings. During investigation, statements of the responsible persons/partners of Appellant No.1 (i.e. Appellant No.2 & 3) were recorded wherein they categorically admitted evasion of central

Page No. 7 of 13

excise duty by clearing final products of Appellant No. 1 without recording manufacture and clearance of excisable goods in their statutory records; also without issuance of invoices; without payment of central excise duty and without obtaining central excise registration. The statements of some of the buyers were also recorded wherein they admitted purchase of excisable goods without receipt of invoice and without payment of central excise duty. It is also a fact that the Appellant No.2 & 3 and the buyers of the Appellant No. 1 had not at any point of time, rebutted the oral and documentary evidences resumed during the investigation and have never stated to have given their statements under duress and/or their statements were not voluntary. From the documentary evidences viz. seized diaries (Ughrani books) of the Appellant No. 1 and statements of Appellants No. 2 & 3 and their buyers, it is conclusively established that the unit had clandestinely removed the excisable goods without recording actual production and clearance thereof and suppressed these facts with intent to evade payment of central excise duty. These are substantial and admissible evidences in the form of documentary (3 diaries) and oral evidences on record resumed from the Appellant No. 1. I find that the investigation has clearly corroborated evidences and proved beyond doubt that the unit has evaded Central Excise duty as detailed in SCN.

8.1. I find that the appellants have willfully, intentionally and deliberately avoided to follow requirement of Central Excise Law while removing the excisable goods, and unlawful means were adopted by them with intent to evade payment of Central Excise duty. All the above facts decisively conclude that the removals of excisable goods were of clandestine nature which resulted in loss of Government Revenue. The evasive mind and *mens-rea* of the Appellants are clearly established. Therefore, I hold that the removal of excisable goods in this case was of clandestine nature with intent to evade payment of Central Excise duty.

8.2. I also find that admitted facts need not be proved as held by the Hon'ble Apex Court in the case of Systems & Components Private Limited reported as 2004 (165) ELT 136 (SC); by the Hon'ble CESTAT in the cases of Alex Industries reported as 2008 (230) ELT 0073 (Tri-Mumbai), M/s. Divine Solutions reported as 2006 (206) E.L.T. 1005 (Tri. (Chennai), wherein it has been consistently held that Confessional statements would hold the field. Hon'ble CESTAT in the case of M/s. Karori Engg. Works reported as 2004 (166) E.L.T. 373 (Tri. Del.), has also held that "confessional statement is a substantial piece of evidence, which can be used against the maker."

in the

8.3 I find that the Appellant No. 1, accepting central excise duty liability, deposited Rs. 20,00,000/- towards Central Excise duty on different dates without

Page No. 8 of 13

Sd

9

protest, which implies that the Appellants have accepted liability to pay Central Excise duty during investigation, after detection of the case by the department. The documentary and oral evidences in the case, established beyond doubt that Appellant No.1 had indulged in illicit manufacture and clearance of Hardware items and Appellant No. 2 and Appellant No. 3 had abetted appellant No.1 in doing so. I find that the statements made by them are inculpable and valid evidences also because they are voluntary. These statements have been corroborated with the documentary evidences (3 diaries) resumed during search operation, which gave details of clearances and modus operandi adopted by the Appellants.

8.4 I find that the ratio of the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in the case of CCE, Mumbai Vs. M/s. Klavert Foods India Pvt. Ltd reported as [2011-TIOL-76-SC-CX], is applicable in the present case, wherein it is held that:-

"18. During the course of arguments learned counsel appearing for the respondent submitted before us that although the aforesaid statements of Managing 'Partner of the Company and other persons were recorded during the course of judicial proceedings but the same were retracted stalements, and therefore, they cannot be relied upon. <u>However, the statements were recorded by the Central Excise Officers and they were not police officers. Therefore, such statements made by the Managing Partner of the Company and other persons containing all the details about the functioning of the company which could be made only with personal knowledge of the respondents and therefore could not have been obtained through coercion or duress or through dictation. We see no reason why the aforesaid statements made in the circumstances of the case should not be considered, looked into and relied upon.</u>

19. We are of the considered opinion that it is established from the record that the aforesaid statements were given by the concerned persons out of their own volition and there is no allegation of threat, force, coercion, duress or pressure being utilized by the officers to extract the statements which comborated each other. Besides, the Managing Partner of the Company on his own volition deposited the amount of Rs. 11 lakhs towards excise duty and therefore in the facts and circumstance of the present case, the aforesaid statement of the counsel for the respondents cannot be accepted. This fact clearly proves the conclusion that the statements of the concerned persons were of their volition and noi outcome of any duress.

(Emphasis supplied)

8.5



8.5 It is also settled legal position that once the case of clandestine removals of excisable goods in the manner it has been executed in the current case is established, it is not necessary to prove the same with mathematical or clinical precision. In this regard, I rely upon the following case-laws:-

Page No. 9 of 13

Madras and others Vs. D. Bhoormull - 1983 (13) E.L.T. 1631 (S.C.).

"The law does not require the prosecution to prove the impossible. All that it requires is the establishment of such a degree of probability that a prudent man may, on its basis, believe in the existence of the fact in issue. Thus legal proof is not necessarily perfect proof often it is nothing more than a provisiont man's estimate as to the probabilities of the case."

(ii) Shah Guman Mal Vs. State of AP - 1983 (13) E.L.T. 1546 (S.C.).

"Department is not required to prove its case with mathematical precision to a demonstrable degree....... All that it requires is the establishment of such a degree of probability that a prudent man may, on its basis, believe in the existence of the fact in issue. Thus, legal proof is not necessarily perfect proof, often it is nothing more than a prudent man's estimate as to the probabilities of the case."

8.6 Accordingly, I hold that Appellant No. 1 is liable to pay Central Excise duty under the provision of Section 11 A(4) of the Act as has been held in the impugned order. It is natural consequence that the confirmed demand is required to be paid along with Interest at applicable rate under the provisions of Section 11AA of the Act and for acting in the above detailed manner with intent to evade payment of duty, the Appellant No. 1 is also liable to penalty equal to duty so evaded, under Rule 25 of the Rules read with Section 11 AC of the Act, as has been held in the impugned order.

9. The Appellant No. 1 has pleaded that the central excise duty has been demanded by taking into consideration the gross value charged by the appellant No. 1 under pakka bills and has requested to grant cum-duty price benefit in respect of removals of goods. The appellant has not submitted copies of pakka bills to the adjudicating authority to substantiate their claim. In case of Kachcha Bills, I find that the Hon'ble Supreme Court in the case of Amrit Agro Industries Ltd. Vs. CCE, Ghaziabad reported at 2007(210) ELT-183(SC) after considering the decisions in the matter of Shri Chakra Tyres and Maruti Udyog relied upon by the appellants, has held that "unless it has been shown by the manufacturer that the price of the goods includes the excise duty payable by him, no question of exclusion of duty element from the price for oetermination of value under section 4(4)(d)(ii) will arise."

9.1 In the case of M/s. Dhillon Kool Drinks and Beverages Ltd. reported as 2011 (263) ELT 241 (T) also, it has been held that cum-duty price benefit cannot to be extended in cases where duty/ tax evasion has occurred on account of fraud, collusion, willful mis-statement, suppression of facts or contravention of any of the provisions with intent to evade payment of duty/ tax, as is the instant case. Similar view has been taken by the CESTAT. Delhi in the case of M/s. Asian Alloys Ltd. Vs. CCE, Delhi-III reported at 2006 (203) ELT 252.

Page No. 10 of 13

9.2 Thus, the appellant's submission to grant cum-duty price benefit in respect of clearances made can't be accepted as it is an admitted fact that Appellant No. 1 has not collected any amount towards Central Excise duty.

10. It has been argued that simultaneous penalty on the partnership firm and the partners can not be imposed. I find that Appellant No. 2 and Appellant No. 3 were the partners of the Appellant No. 1 - a partnership firm. The Appellant No. 2 has clearly admitted that they have cleared the dutiable goods without raising invoices and without payment of central excise duty, even after crossing the threshold limit of SSI exemption. The Appellant No. 3 has also clearly admitted that he was maintaining the diaries (Ughrani Books) and had recorded the transactions made without bills and without payment of central excise duty. I find that both these appellants were fully aware that what they are doing is absolutely wrong under the Act and the Rules and the goods they have dealing with in this manner were liable to confiscation. They were also fully aware that these excisable goods have not suffered proper Central Excise duty, and therefore, the said goods were liable to confiscation. Looking to the facts and circumstantial evidences, both of these appellants have rendered themselves liable for penalty under Rule 26(1) & (2) ibid as they have abetted Appellant No. 1 in evasion of central excise duty.

10.1 I find that Hon'ble CESTAT, Ahmedabad in the case of Yunusbhai Samsuddin Devdiwala reported as 2016 (334) ELT 120 (Tri.-Ahmd.) has already held that personal penalty upon partners is imposable in addition to penalty imposed on the partnership firm.

10.2 I also find that the Hon'ble Madras High Court in the case of C. Eswaran reported as 2014 (306) E.L.T. 264 (Mad.) has held as under:-

*8. It is true that the statutory authority imposed penalty on the firm as well as on the partner. The finding recorded by the original authority was confirmed in appeal. The legality and correctness of the order was once again tested by the CESTAT. The CESTAT being the final fact finding authority arrived at a conclusion that there was clinching evidence to show that the appellant imported the weaving looms by fabricaling the records and engraving the year of manufacture.

The only question raised in the present appeals is as to whether the statutory authority was justified in imposing fine on the firm as well as on the partner.

10. Section 112(a) of the Customs Act. 1962 provides that not only the person who is instrumental in doing a particular act by violating the provisions of the Act but also the person who abets it or commits such act, is also liable for payment of penalty. The goods in question were imported in the name of the firm by name M/s. Sri Ram Tex. The appellant in C M A. No. 811 of 2012 in his capacity as the partner abetted the firm to commit the offence. Therefore, the statutory authority was fully justified in imposing fine on the firm as well as on the partner.



(Emphasis supplied)



52

A Physical Print, A restriction, for state and the state of the

50

10.3. In light of the facts of this case and legal position as above, the imposition of penalty on Appellant No. 2 & Appellant No. 3 under Rule 26 of the Rules, is legal and proper. However, the quantum of Rs. 4 lakhs on each is very high. To meet the ends of justice, personal penalty is reduced to Rs. 1 lakh on each of the Appellant No. 2 and Appellant No. 3.

12

It has been submitted that when Appellant No. 1 has admitted the 11. duty liability and has also made payment of duty, there was no requirement of issuance of Show Cause Notice and proceedings initiated should have been concluded against the co-noticees also. I find that the instant case involves the ingredients of suppression of facts, clandestine manufacture and clearance of excisable goods, and therefore provisions of Section 11AC(1)(d) would be applicable for conclusion of proceedings. Accordingly, Appellant No. 1 was required to pay entire duty demanded in the Show Cause Notice alongwith interest payable thereon and also reduced penalty @ 15% of duty before issue of SCN but the Appellant No. 1 did not pay full interest and penalty @ 15% of duty and hence, SCN was issued correctly. Appellant No. 1 did not pay penalty @ 15% within 30 days of communication of the Show Cause Notice also, Section 11(1)(e) of the Act provides that if Central Excise duty alongwith interest in full have been paid within 30 days of the communication of the SCN, then proceedings can be concluded. However, the Appellant No. 1 did not pay penalty @ 15% even within 30 days of receipt of SCN and hence the lower adjudicating authority had no option but to adjudicate the SCN. He has given the Appellant No. 1 option to pay 25% penalty within 30 days of receipt of impugned order, however, Appellant No. 1, has not paid any amount towards penalty within 30 days from the communication of impugned order also. Therefore, the proceedings could not have been concluded before issue of SCN or even after issue of SCN and hence, the issuance of impugned order is justified.

12. In view of above findings, I reject the appeals and uphold the impugned order except as modified at Para 10.3 above.

15.4.

अपीलकलीओ दवार। दर्ज की गई अपीलों का निपटास उपरोक्त तरीके से किया जाता

31

12.1. The appeals filed by the appellants stand disposed off in above terms.

सत्यापित

ाग्त, एम. पोपट, (अभील)

(कगार संतोष)

आयुक्त (अपील्स)

Page No. 12 of 13

By Speed Post

10		
1	M/s Kaveri Engineers, Shivam Industrial Main Road, Plot No. 17, Survey No. 29, Vavdi, Near Falcon Pump, Shivam Chowk, Behind Hotel Krishna Park, Gondal Road, Rajkot – 360 007	मैं कावेरी इंजीनियरस, शिवम इंडॉस्ट्रेयल मैन रोग, फ्लॉट ने. १७, सर्व ने. २९, वावडी, फाल्फोन परम्प के पास, शिवम चौंक, होटल कृष्णा पार्क के पीछे, गौडल रोड, राजकोट
2	Shri Rajanbhai Santoki, Partner, M/s. Kaveri Engineers, Shivam Industrial Main Road, Plot No 17, Survey No. 29, Vavdi, Near Falcon Pump, Shivam Chowk, Behind Hotel Krishna Park, Gondal Road, Rajkot – 360 007	श्री राजनमाई संतोकी, पार्टनर, में. कावेरी इंजीनियरस, शिवम इंडस्ट्रियल मैन रोड, प्लॉट नं. १७, सर्वे नं. २९, वावडी, फाल्कोन परुप के पास, शिवम चौंक, होटल कृष्णा पार्क के पीछे, गॉडल रोड, राजकोट
3	Shri Ashokbhai L. Patel, Partner, M/s. Kaveri Engineers, Shivam Industrial Main Road, Piot No. 17, Survey No. 29, Vavdi, Near Falcon Pump, Shivam Chowk, Behind Hotel Krishna Park, Gondal Road, Rajkot – 360 007	श्री अशोकभाइ एल. पटेल, पार्टनर, में. कावेरी इंजीनियरस. शिवम इंडस्ट्रियल मैन रोड, प्लॉट नं. १७, सर्व नं. २९, चावडी, फाल्कोन पम्प के पास, शिवम चौक, होटल कृष्णा पार्क के पीछे, गॉडल रोड, राजकोट

Copy to:

The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad
 The Commissioner, GST & Central Excise, Rajkot Commissionerate, Rajkot.

3. The Assistant Commissioner, GST & Central Excise, Division-I, Rajkot.

4. Guard File.





:: By Speed Post ::

फ़ाइल संख्या /File No. V2/208/RAJ/2016

सेवामें / To,

M/s. Rajanbhai Santoki,, Partner of Kaveri Engineers, Shivam Industrial Main Road, Plot No. 17, Survey No. 29,, Vavdi Nr. Falcon Pump, Shivam Chowk Gondal RoadRajkot.

Personal Hearing / व्यक्तिगत सुनवाई

महोदय / Gentleman,

विषय: अपील से संबन्धित व्यक्तिगत सुनवाई के संदर्भ में. Subject: Personal Hearing in Appeal Petition...m/r.

आयुक्त (अपील-III), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट, द्वारा निर्देशित किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरकर्ता आपको सूचित करते हैं कि आपके द्वारा दर्ज की गई निम्नलिखित अपील' अपीलों के संदर्भ व्यक्तिगत सुनवाई, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित दिनांक एवं समय पर निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्त पते पर नियत समय पर आपकी उपस्थिति अपेक्षित है।

The undersigned has been directed by the Commissioner (Appeals-III), Central Excise & Customs, Rajkot, to intimate you to appear before the appellate authority for personal hearing in the case of following appeals, on the below mentioned date and time, at the above mentioned address.

क्रम संख्या/ Sr. No.	अपील संख्या/ Appeal Number	अपीलार्थी का नाम/ Name of Appellant / Respondent	मूल आदेश संख्या एवं दिनांक/ Order in Original No. and date	दिनांक एवं समय / Date and time
01	V2/208/RAJ/2016	M/s. Rajanbhai Santoki,	02 & 03/ADC/BKS/2016-17 Dtd. 16.05.2016	09.03.2017 at 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत सुनवाई में अपनी उपस्थिति की पुष्टि हेतु इस कार्यालय को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सूचित करें। इसके अलावा, जहाँ तक संभव हो, अपील जापन-पत्र में प्रेषित लिखित प्रस्तुतियाँ तथा उसके बाद यदि अन्य कोई प्रस्तुतियाँ दर्ज कराई गयी हैं तो उन सभी प्रस्तुतियाँ की सॉफ्ट कॉपी अपील के प्रसरकरण में सुगमता के लिए एक CD/ Email id पर उपलब्ध करायें।

Further, it is requested to confirm the schedule of your appearance in the personal hearing to this office, one day in advance. Also, wherever possible, please provide the soft copies of the written submissions made in the appeal memorandum alongwith any submission made thereafter on a CD / Email id mentioned above, for the ease in processing of the appeal.

0/0

भवदीय / Yours sincerely. ant in अधीक्षक (अपील)/ Superintendent (Appeals)



22.02.2017

दिनाक: / Date :



::

फ़ाइल संख्या /File No. V2/208/RAJ/2016

12

PH At Rajkot

22.02.2017

दिनांक: / Date :

सेवामें / To, The Additional Commissioner, Central Excise, Rajkot.

Personal Hearing / व्यक्तिगत सनवाई

महोदय / Sir,

विषय: अपील से संबन्धित व्यक्तिगत सुनवाई के संदर्भ में. Subject: Personal Hearing in Appeal Petition...m/r.

आयुक्त (अपील-III), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट, दवारा निर्देशित किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरकर्ता आपको सूचित करते हैं कि आपके द्वारा दर्ज की गई निम्नलिखित अपील/ अपीलों के संदर्भ व्यक्तिगत सुनवाई, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित दिनांक एवं समय पर निर्धारित की गई है। अतः उपरोक्त पते पर नियत समय पर आपकी उपस्थिति अपेक्षित है।

The undersigned has been directed by the Commissioner (Appeals-III), Central Excise & Customs, Rajkot, to intimate you to appear before the appellate authority for personal hearing in the case of following appeals, on the below mentioned date and time, at the above mentioned address.

क्रम संख्या/ Sr. No.	अपील संख्या/ Appeal Number	अपीलार्थी का नाम/ Name of Appellant / Respondent	मूल आदेश संख्या एवं दिनांक/ Order in Original No. and date	दिनांक एवं समय / Date and time
01	V2/208/RAJ/2016	M/s. Rajanbhai Santoki,	02 & 03/ADC/BK5/2016- 17 Dtd. 16.05.2016	09.03.2017 at 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत सुनवाई में अपनी5 उपस्थिति की पुष्टि हेतु इस कार्यालय को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सुचित करें।

Further, it is requested to confirm the schedule of your appearance in the personal hearing to this office, one day in advance.

अवदीय / Yours faithfully,

0/0

अधीक्षक (अपील)/ Superintendent (Appeals)

57



::आयुक्त (अपील-III) का कार्यालय,केंद्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS-III), CENTRAL EXCISE, द्वितीय तल. बेल्दीय उत्पाद शुल्क अवन / 2nd Floor, Central Excise Bhavan, रेस कोसे रिंग रोड, / Race Course Ring Road, <u>राजकोट - 360001 / Rajkot - 360 001</u> Tele / Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cesappealarajkot@gmail.com

फा.स. V2/208/RAJ/2016

विनांक: 31.08.2016

प्रति / To, M/s. Rajanbhai Santoki,, Partner of Kaveri Engineers, Shivam Industrial Main Road, Plot No. 17, Survey No. 29,, Vavdi Nr. Falcon Pump, Shivam Chowk Gondal Road, Rajkot.

> विषय:Sub.:आपके दवारा मूल आदेश (OIO) सं. 02 & 03/ADC/BKS/2016-17 दिनाक 16.05.2016, के विरुद्ध फाइल की गई अपील जो की Additional Commissioner, Central Excise, Rajkot दवारा पारील किया गया है 1

महाशय/Gentleman,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपकी अपील इस कार्यालय में दिनाक

22.08.2016 को प्राप्त हुई तथा उसे अपील संख्या 208/RAJ/2016 से पंजीकृत किया गया है।

On the above subject, it is to inform you that your appeal has been received by this office on 22.08.2016 which has been registered and allotted Appeal No. 208/RAJ/2016.

आपसे आग्रह है कि भविष्य में सभी पत्राचार में उपरोक्त अपील संख्या अवश्य लिखे।

You are requested to quote above Appeal No. in all future correspondence without fail.

इस कार्यालय के सुविधा के लिए तथा अपील के शीघ्र निपटारा हेतु, अपीलकर्ता स्वेच्छा से अपील

मेमो / लिखित निवेदन और संबंधित case-laws को CD में अथवा Email दवारा भेजने की कपा करे।

The appellants for the sake of convenience of this office and the expeditious disposal of appeal may also voluntarily like to submit soft copy of their appeal memorandums/written submission on a CD / email mentioned above along with the case-laws cited.

4. The Appeal should be filed within 60 days from the date of its communication as per the provision of Section 35(1) of the Central Excise Act, 1944, however the Appeal filed by you is late by _____ days. Inspite of this you have not filed any request for condonation of delay for filing the appeal.

भवदीय Yours sincerely.

्रिप्त एम पोपट / N.M. Popat] अधीक्षक (अपील- III), Superintendent (Appeals-III)



प्रति / To, The Additional Commissioner, Central Excise. Rajkot.

> विषय - मूल आदेश (OIO) सं. 02 & 03/ADC/BKS/2016-17, दिनांक, 16.05.2016 के विरोज मैसर्स Rajanbhai Santoki, द्वारा दायर की गई अपील।

> Subject: Appeal filed by M/s. Rajanbhai Santoki, against OIO No. 02 & 03/ADC/BKS/2016-17 dated. 16.05.2016

महोदय, Sir.

कृपया, इस पत्र के साथ संलग्न अपील सं. 208/RAJ/2016 दिनांक, 22.08.2016 की प्रति देखें । अपील कर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर पैरा अनुसार टिप्पणियां आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है ।

Please find enclosed herewith a copy of Appeal No. 208/RAJ/2016 dated 22.08.2016 for your information and para wise comments on the point raised by the party.

निम्नलिखित बिदुओं पर सूचनाएं दी जाए --

इसी प्रकार के मामलों में CESTAT/HC/SC द्वारा पारित किए गए आदेशों/ नियमों की प्रतियां ।

२. अपील कर्ता की वित्तीय स्थिति ।

The following information may also be supply with your comments:-

- Copies of Orders/Case Laws passed by CESTAT/HC/SC in similar issues. (i)
- Financial Position of Appellant: (ii)

भवदीय. Yours faithfully.

संलग्न - ग्रथांपरी । Encl.: As above.

9111 [एन एम पोपट / N.M. Popat] अधीक्षक (अपील-III), Superintendent (Appeals-III)

RAJANBHAI BHAGVANJI SANTOKI

FLAT NO.202, A BLOCK, BACKBONE HEIGHT, NANA MAVA MAIN ROAD, RAJKOT.

ur and and and a x q, ur all q, manaliz Commissiones (Appents) C. Ex. & Cos. R AJKOT 2.7 Act 2005 ула бъл В ЕСЕЛУЕД

By Hand Delivery Date: 22.08.2016

To The Commissioner (Appeals), Central Excise, Race Course Ring Road, RAJKOT.

Sir,

Sub; -

Appeal filed by against the Order in Original No.2 & 3/ADC/BKS/2016-17 dated 16/18.05.2016 passed by The Additional Commissioner, Central Excise, Rajkot; M/Reg.

On being aggrieved with the said order, the Appellant is here by filling an Appeal in the prescribed Form EA-1 along with condonation of Delay, in duplicate. The Appeal is duly affixed with court fees stamps of Rs.5/- as required.

The Number of Appeal may kindly be intimated.

We wish to be heard in person. Therefore kindly intimate the date of personal hearing in the matter.

Thanking you.

Yours faithfully,

R. B. Patel

(Rajanbhai Santoki)